



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1592]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 18, 2011/श्रावण 27, 1933

No. 1592]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 2011/SARVANA 27, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2011

का.आ.1910(अ).—यतः मै.जीआईएफटी एसईजेड लिमिटेड ने गुजरात राज्य में गांधीनगर जिले के ग्राम फिरोजपुर एवं रतनपुर में बहु सेवा के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 7 जनवरी, 2008 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र को उपर्युक्त स्थान पर विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

तालिका

क्र. सं.	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	फिरोजपुर	2(भाग)	39.0823
2.	-	2-डी(भाग)	0.1696
3.	-	12	0.2732
4.	-	13	1.2039
5.	-	15	0.5261
6.	-	16	0.2630
7.	-	18	0.5868
8.	-	19	0.5666
9.	-	22(भाग)	12.0600
10.	रतनपुर	260	0.5232
11.	-	261	0.5946
12.	-	262(भाग)	47.4093
13.	-	262/1(भाग)	2.1800
कुल			105.4386
			हेक्टेयर

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

1. विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त —अध्यक्ष, पदेन
2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, —सदस्य, पदेन  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग  
या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव,  
भारत सरकार से कम नहीं होगा
3. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय —सदस्य, पदेन  
क्षेत्राधिकार रखने वाले क्षेत्रीय संयुक्त  
विदेश व्यापार महानिदेशक
4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय —सदस्य, पदेन  
क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क  
आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त  
अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त  
आयुक्त से कम नहीं होगा
5. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय —सदस्य, पदेन  
क्षेत्राधिकार रखने वाले आयुक्त आयुक्त  
अथवा उसका नामिती जिसका स्तर  
संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा
6. निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, —सदस्य, पदेन  
बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार
7. राज्य सरकार द्वारा नामित किए —सदस्य, पदेन  
जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर  
संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा
8. जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि —विशेष आमंत्रित  
और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का  
28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग  
करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 2011 को  
उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त  
विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962  
का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना  
जाएगा।

[फा. सं. एफ. 1/145/2007-एसईजेड]

अनूप वधावन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2011

**S.O. 1910(E).**—Whereas M/s. GIFT SEZ Limited, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for multi-services at Villages Phirozpur and Ratanpur, District Gandhinagar in the State of Gujarat;

And whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and

maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 7th January, 2008;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of Rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the following area at above location with survey numbers given below in the Table, as a Special Economic Zone, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Phirozpur	2 (part)	39.0823
2.	-	2-D (part)	0.1696
3.	-	12	0.2732
4.	-	13	1.2039
5.	-	15	0.5261
6.	-	16	0.2630
7.	-	18	0.5868
8.	-	19	0.5666
9.	-	22 (part)	12.0600
10.	Ratanpur	260	0.5232
11.	-	261	0.5946
12.	-	262 (part)	47.4093
13.	-	262/1 (part)	2.1800
Total			105.4386 hectares

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of Section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1. Development Commissioner of the Special Economic Zone —Chairperson  
*ex-officio*
2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India —Member,  
*ex-officio*
3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade, having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone —Member,  
*ex-officio*
4. Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner —Member,  
*ex-officio*

5. Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner

—Member,  
*ex-officio*

6. Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India

—Member,  
*ex-officio*

7. Two Officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the State Government

—Members,  
*ex-officio*

8. Representative of the Developer of the Zone

—Special  
Invitee

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 18th day of August, 2011 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F. 1/145/2007-SEZ]

ANUP WADHAWAN, Jt. Secy.